केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री ने 'बाल विवाह मुक्त भारत' अभियान की शुरुआत की 'बाल विवाह मुक्त भारत' अभियान

यह अभियान सभी नागरिकों से बाल विवाह का सक्रिय रूप से विरोध करने का आह्वान करता है और यह महिला एवं बाल विकास मंत्रालय तथा विभिन्न अन्य मंत्रालयों के बीच एक सहयोगात्मक प्रयास है।

अभियान के बारे में

• फोकस क्षेत्र: बाल विवाह के उच्च बोझ वाले सात राज्यों और लगभग 300 उच्च बोझ वाले जिलों में।

• सहयोगात्मक दृष्टिकोण: प्रत्येक राज्य और केंद्र शासित प्रदेश से 2029 तक बाल विवाह की दरों को 5% से कम करने के उद्देश्य से एक कार्य योजना तैयार करने का आह्वान।

• बाल विवाह मुक्त भारत पोर्टल: एक अभिनव ऑनलाइन प्लेटफ़ॉर्म जो नागरिकों को बाल विवाह की घटनाओं की रिपोर्ट करने, शिकायत दर्ज करने और देश भर में बाल विवाह निषेध अधिकारियों (CMPO) के बारे में जानकारी प्राप्त करने में सक्षम बनाता है।

भारत में बाल विवाह की स्थिति

• बाल विवाह में कमी: एनएफएचएस-5 के अनुसार, बाल विवाह 2005-06 में 47.4% से घटकर 2015-16 में 26.8% हो गया है।

• घरेलू संपत्ति के अनुसार भिन्नता: एनएफएचएस-5 के अनुसार, निम्नतम पंचमांश में 40% महिलाएँ 18 वर्ष की आयु से पहले विवाह कर लेती हैं, जबकि उच्चतम पंचमांश में केवल 8% महिलाएँ विवाह कर लेती हैं।

• उच्च प्रचलन वाले राज्य: पश्चिम बंगाल, बिहार, त्रिपुरा, झारखंड, असम, आंध्र प्रदेश, राजस्थान और तेलंगाना।

सरकार द्वारा उठाए गए कदम

• बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 (पीसीएमए): यह उन बाल विवाहों पर रोक लगाता है जहाँ महिलाएँ 18 वर्ष से कम और पुरुष 21 वर्ष से कम आयु के हैं।

• बाल अधिकारों पर संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन: भारत एक हस्ताक्षरकर्ता है।

• राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर): बाल विवाह से लड़ने के लिए जागरूकता कार्यक्रम चलाता है।

लेबनान में इजरायल और हिजबुल्लाह ने युद्ध विराम समझौता किया

इजरायल और लेबनान ने 13 महीने से चल रहे सीमा संघर्ष को समाप्त करने के लिए अमेरिका समर्थित प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया है, जो एक पूर्ण युद्ध में बदल गया।

समझौते के बारे में

• युद्ध विराम समझौता 2006 में संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद (यूएनएससी) द्वारा पारित संकल्प 1701 के प्रावधानों पर आधारित है।

• इजरायल: इजरायल रक्षा बल (आईडीएफ) 60 दिनों के भीतर ब्लू लाइन पर वापस आ जाएगा

o ब्लू लाइन को संयुक्त राष्ट्र द्वारा 2000 में निर्धारित किया गया था और यह इजरायल और लेबनान के बीच एक वास्तविक सीमा के रूप में कार्य करता है।

• हिजबुल्लाह: लिटानी नदी के दक्षिण से सभी लड़ाकों और हथियारों को हटाना।

• लेबनान: लेबनानी सेना और लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल (यूएनआईएफआईएल) दक्षिण लेबनान में आईडीएफ और हिजबुल्लाह की जगह लेंगे।

o सरकार की सहमति के बिना कोई विदेशी सेना या हथियारों की आपूर्ति नहीं की जा सकती।

संकल्प 1701 के बारे में

• संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के संकल्प ने 2006 के इज़राइल-हिज़्बुल्लाह युद्ध को समाप्त कर दिया।

• यह निर्धारित करता है कि लेबनान की लिटानी नदी के दक्षिण में एकमात्र सशस्त्र समूह लेबनानी सेना और संयुक्त राष्ट्र शांति सेना (लेबनान में संयुक्त राष्ट्र अंतरिम बल - यूनिफ़िल) होनी चाहिए।

बढ़ती पानी की मांग और भूजल की कमी के कारण पृथ्वी की धुरी 31.5 इंच झुक गई: अध्ययन

जियोफिजिकल रिसर्च लेटर्स में प्रकाशित एक हालिया अध्ययन से पता चलता है कि अत्यधिक भूजल निष्कर्षण ने पृथ्वी के घूर्णन ध्रुव को स्थानांतरित कर दिया है, जो ग्रह पर मानवीय गतिविधियों के प्रभाव को उजागर करता है।

अध्ययन के मुख्य निष्कर्ष

• 1993 और 2010 के बीच, अत्यधिक भूजल निष्कर्षण के कारण पृथ्वी का घूर्णन ध्रुव 80 सेमी पूर्व की ओर स्थानांतरित हो गया, जिसने ग्रह के द्रव्यमान वितरण को बदलकर समुद्र के स्तर में 0.24 इंच की वृद्धि में योगदान दिया।

• पृथ्वी की घूर्णन धुरी में बदलाव भूजल के जलभृतों से महासागरों की ओर जाने के कारण होता है।

o यह बदलाव 4.36 सेमी प्रति वर्ष की दर से हुआ, जिसने पिछले जलवायु मॉडल को चुनौती दी जो मुख्य रूप से बर्फ की चादरों के पिघलने पर केंद्रित थे।

• दुनिया के अधिकांश महासागरों में लगभग 10 मिमी की वृद्धि देखी गई, लेकिन उत्तर-पश्चिमी भारत और पश्चिमी उत्तरी अमेरिका में भूजल की कमी वाले क्षेत्रों से सटे भारतीय और प्रशांत महासागर में समुद्र के स्तर में गिरावट देखी गई।

पृथ्वी की गति के बारे में

• पृथ्वी की दो तरह की गति होती है: घूर्णन और परिक्रमण।

• परिक्रमण पृथ्वी की अपनी धुरी के चारों ओर गति है, जबकि परिक्रमण पृथ्वी की एक निश्चित कक्षा में सूर्य के चारों ओर गति है।

• पृथ्वी की धुरी एक काल्पनिक रेखा है जो अपनी कक्षा से 66½° के कोण पर झुकी हुई है।

o पृथ्वी के झुकाव के प्रभाव

 पृथ्वी के घूमने के कारण दिन और रात होते हैं, जबकि इसकी परिक्रमा के कारण मौसम बदलते हैं।

 यह गर्मी वितरण में भिन्नता भी पैदा करता है, जिससे मौसम और जलवायु क्षेत्र बनते हैं।

केंद्र सरकार ने पीएम ई-ड्राइव योजना के दूसरे चरण को अधिसूचित किया

हाल ही में, केंद्रीय भारी उद्योग मंत्रालय ने एल5 श्रेणी के इलेक्ट्रिक 3-व्हीलर्स के लिए सब्सिडी लाभ की अनुमति देने के लिए पीएम इलेक्ट्रिक ड्राइव क्रांति इन इनोवेटिव व्हीकल एन्हांसमेंट (पीएम ईड्राइव) योजना में आंशिक संशोधनों को अधिसूचित किया है।

अधिसूचना की मुख्य विशेषताएं

• प्रति वाहन प्रोत्साहन:

o 1 अप्रैल, 2024 - 7 नवंबर, 2024: ₹5,000/kWh (प्रति वाहन ₹50,000 तक सीमित)।

o 8 नवंबर, 2024 - 31 मार्च, 2026: ₹2,500/kWh (प्रति वाहन ₹25,000 तक सीमित)।

• प्रोत्साहन प्राप्त करने के लिए अधिकतम एक्स-फैक्ट्री कीमत: ₹5 लाख।

• निधि आवंटन: ₹715 करोड़।

पीएम ई-ड्राइव योजना के बारे में

• उद्देश्य: ईवी की खरीद के लिए अग्रिम प्रोत्साहन प्रदान करके ईवी को अपनाने में तेजी लाना, साथ ही ईवी के लिए आवश्यक चार्जिंग बुनियादी ढांचे की स्थापना की सुविधा प्रदान करना।

•समय अवधि: 2024-26.

• लक्ष्य

o ई-2डब्ल्यू, ई-3डब्ल्यू और ई-बसों को समर्थन।

o ई-4डब्ल्यू, ई-बसों और ई-2डब्ल्यू/3डब्ल्यू के लिए फास्ट चार्जर की स्थापना।

• नोडल मंत्रालय: केंद्रीय भारी उद्योग मंत्रालय।

• 3 घटक

o सब्सिडी: ई-2डब्ल्यू, ई-3डब्ल्यू, ई-एम्बुलेंस, ई-ट्रक और अन्य नई उभरती हुई ईवी श्रेणियों के लिए मांग प्रोत्साहन;

o पूंजीगत परिसंपत्तियों के निर्माण के लिए अनुदान: ई-बसें, चार्जिंग स्टेशनों के नेटवर्क की स्थापना और एमएचआई की परीक्षण एजेंसियों का उन्नयन; और

o आईईसी (सूचना, शिक्षा और संचार) गतिविधियों और परियोजना प्रबंधन एजेंसी (पीएमए) के लिए शुल्क सहित योजना का प्रशासन।

केंद्र ने 'टमाटर ग्रैंड चैलेंज (टीजीसी)' के विजेताओं के लिए "वित्त पोषण और सलाह" की घोषणा की

टीजीसी टमाटर आपूर्ति श्रृंखला को स्थिर करने के लिए अभिनव, स्केलेबल समाधान चाहता है।

• इसे शिक्षा मंत्रालय (नवाचार प्रकोष्ठ) के सहयोग से उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा 2023 में लॉन्च किया गया था।
• टमाटर, प्याज और आलू (सामूहिक रूप से (TOPs) के रूप में संदर्भित) के साथ सभी फसलों में कृषि वस्तुओं में भारी उतार-चढ़ाव देखा गया है।

TOPs के बारे में

• TOPs भारत में सबसे अधिक खेती, उत्पादन और खपत की जाने वाली सब्जियाँ हैं।

• TOPs उपभोक्ता मूल्य सूचकांक (CPI) सब्जियों की श्रेणी का एक तिहाई से अधिक हिस्सा बनाते हैं।

TOPs की कीमतों में व्यापक उतार-चढ़ाव से जुड़े मुद्दे

• मौसमी उत्पादन: कम उत्पादन के कारण आपूर्ति की कमी और उच्च कीमतें होती हैं, जबकि बंपर फसल के कारण कीमतें कम होती हैं।

• प्राकृतिक कारक: मौसम के झटके और कीटों के हमले अस्थिरता को बढ़ाते हैं।

• भंडारण पहुंच: सीमित भंडारण सुविधाएँ (ज्यादातर निजी स्वामित्व वाली) जो कि यूपी, पंजाब, पश्चिम बंगाल, गुजरात (सीआईआई रिपोर्ट) सहित कुछ राज्यों में केंद्रित हैं।

• असंगठित बाजार: TOP के लिए उत्पादकों को उपभोक्ताओं से जोड़ने के लिए दूध सहकारी समितियों जैसे मजबूत नेटवर्क की कमी।

• ऑपरेशन ग्रीन्स को लागू करने में मुद्दे: विभिन्न प्रकार टॉप्स और बढ़ती परिस्थितियाँ विपणन हस्तक्षेप को जटिल बनाती हैं। टॉप्स के मूल्य स्थिरीकरण के लिए पहल • ऑपरेशन ग्रीन्स: इसे टॉप्स की मूल्य अस्थिरता को संबोधित करने के लिए ऑपरेशन फ्लड की तर्ज पर शुरू किया गया था और इसे अन्य फलों और सब्जियों (टॉप से टोटल) तक बढ़ाया गया था। • ग्रामीण कृषि बाजार (ग्राम): ग्रामीण हाट (ग्रामीण बाजार) को ग्रामीण कृषि बाजार (ग्राम) में विकसित किया जा रहा है ताकि किसान सीधे अपनी उपज बेच सकें। • बागवानी के एकीकृत विकास के लिए मिशन (एमआईडीएच): बागवानी के समग्र विकास के लिए और कम लागत वाली प्याज भंडारण संरचना में सहायता करता है। • अन्य पहल: ग्रामीण गोदामों के लिए कृषि विपणन अवसंरचना (एएमआई), किसान रेल सेवा, मूल्य स्थिरीकरण कोष (पीएसएफ), आदि।

भारतीय रासायनिक परिषद (आईसीसी) को 2024 ओपीसीडब्ल्यू द हेग पुरस्कार प्रदान किया गया

रासायनिक हथियारों के निषेध के लिए संगठन (ओपीसीडब्ल्यू) हेग पुरस्कार रासायनिक सुरक्षा, रासायनिक हथियार सम्मेलन (सीडब्ल्यूसी) के अनुपालन में आईसीसी के योगदान को स्वीकार करता है।

• यह पहली बार है कि पुरस्कार किसी रासायनिक उद्योग निकाय के प्रयासों को मान्यता देता है।

• रासायनिक हथियार सम्मेलन (सीडब्ल्यूसी) लक्ष्यों में ओपीसीडब्ल्यू के योगदान को सम्मानित करने के लिए 2014 में हेग पुरस्कार की स्थापना की गई थी।

रासायनिक हथियार सम्मेलन (सीडब्ल्यूसी) के बारे में

• उत्पत्ति: यह 1997 में लागू हुआ, और वर्तमान में इसके 193 राज्य पक्ष हैं।

o भारत इस सम्मेलन का मूल हस्ताक्षरकर्ता है।

• उद्देश्य: राज्यों द्वारा रासायनिक हथियारों के विकास, उत्पादन, अधिग्रहण, भंडारण, प्रतिधारण, हस्तांतरण या उपयोग पर रोक लगाकर सामूहिक विनाश के हथियारों की एक पूरी श्रेणी को खत्म करना।

• कार्यान्वयन: OPCW कार्यान्वयन निकाय है, जिसका मिशन रासायनिक हथियारों से मुक्त दुनिया को प्राप्त करना है।

o OPCW को 2013 में नोबेल शांति पुरस्कार से सम्मानित किया गया था।

o रासायनिक हथियार एक ऐसा रसायन है जिसका उपयोग अपने विषैले गुणों के माध्यम से जानबूझकर मौत या नुकसान पहुँचाने के लिए किया जाता है।

 विषैले रसायनों को हथियार बनाने के लिए विशेष रूप से डिज़ाइन किए गए युद्ध सामग्री, उपकरण और अन्य उपकरण भी रासायनिक हथियारों की परिभाषा के अंतर्गत आते हैं।

• भारत में कार्यान्वयन: राष्ट्रीय प्राधिकरण रासायनिक हथियार सम्मेलन (NACWC) भारत में सम्मेलन को लागू करने के लिए जिम्मेदार राष्ट्रीय है।

o NACWC की स्थापना रासायनिक हथियार सम्मेलन अधिनियम, 2000 के तहत की गई थी।

भारतीय रासायनिक परिषद (ICC) के बारे में

• के बारे में: भारत के रासायनिक उद्योग की सभी शाखाओं का प्रतिनिधित्व करने वाला शीर्ष राष्ट्रीय निकाय, जिसमें कार्बनिक/अकार्बनिक रसायन, प्लास्टिक और पेट्रोकेमिकल शामिल हैं।

• उत्पत्ति: भारत के रासायनिक उद्योग के विकास को समर्थन देने और उसे आगे बढ़ाने के लिए 1938 में स्थापित।

• उद्योग प्रतिनिधित्व: भारत के 220 बिलियन डॉलर के रासायनिक उद्योग के 80% से अधिक का प्रतिनिधित्व करता है।

हाल ही में, 24 नवंबर को गुरु तेग बहादुर जी का 'शहीदी दिवस' मनाया गया।

गुरु तेग बहादुर जी (1621 - 1675) के बारे में

• उनका जन्म अमृतसर (पंजाब) में हुआ था।

• वे 9वें सिख गुरु थे और एक महान योद्धा, आध्यात्मिक व्यक्तित्व और मातृभूमि के प्रेमी थे।

मुख्य योगदान

• उन्होंने सार्वभौमिक भाईचारे और धार्मिक स्वतंत्रता के संदेश का प्रचार किया।

• उन्होंने अंधविश्वास, जाति-आधारित भेदभाव और अस्पृश्यता के खिलाफ लड़ाई लड़ी।

o उनकी शिक्षाएँ एक मजबूत और जीवंत भारत के निर्माण के लिए प्रेरित करती हैं जो समानता, न्याय, बंधुत्व के स्तंभों पर दृढ़ है

और स्वतंत्रता

• उन्होंने पंजाब में चक नानकी शहर की स्थापना की, जिसे बाद में श्री आनंदपुर साहिब शहर में विस्तारित किया गया।

• उन्हें 'हिंद दी चादर' के दुर्लभ सम्मान से सम्मानित किया गया।

मूल्य

• वीरता, आध्यात्मिकता, नेतृत्व, दृढ़ संकल्प, आदि।